दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, बुधवार 30 जून 2021 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-03, अंक- 270

महत्वपूर्ण एवं खास

गोदावरी नदी में चार छात्र डूबे, तीन शव बरामद

काकीनाडा (आरएनएस)। आंध्र प्रदेश में कोनासीमा क्षेत्र के पी गन्नावरम मंडल में तैराकी के दौरान गोदावरी नदी में डूबे दसवीं कक्षा के चार छात्रों में से तीन के शव निकाल लिये गये। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार , लंकाला गन्नावरम गांव के चार छात्र दसवीं की परीक्षा रद्द होने का जश्न मनाने के लिए नदी में तैरने गये और इसी दौरान नदी में बह गये। उनके घर नहीं लौटने पर माता-पिता ने उन्हें खोजना शुरू किया, तभी नदी के किनारे पर उनके कपड़े और जूते मिले। स्थानीय तैराकों ने तीन छात्रों संथाला पवन, यारामसेट्टी रत्नसागर और बंडारू नवीनकुमार के तीन शवों को निकाल लिया। पुलिस ने कहा कि चौथे छात्र खंडावल्ली विनय के शव का अभी पता नहीं चल पाया है।

मुठभेड़ में लश्कर के टॉप कमांडर समेत 2 आतंकियों को सुरक्षाबलों ने मार गिराया

श्रीनगर (आरएनएस)। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पारिमपोरा इलाके में सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में दो आतंकियों को ढेर कर दिया। जवानों ने लश्कर के टॉप कमांडर अबरार को मार गिराया है। जानकारी के अनुसार इलाके में पिछले 12 घंटे से मुठभेड़ जारी है। सुरक्षाबलों को इलाके में अभी कुछ और आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। इनकी तलाश के लिए अभी ऑपरेशन जारी है। मुठभेड़ में ढेर हुए लश्कर कमांडर नदीम अबरार पर कई जवानों के हत्या का आरोपी था, शव बरामद करने के बाद जवानों ने इसकी पुष्टि की है। मारे गए आतंकियों के पास से गोलाबारूद भी बरामद हुए है।

पीएम ने तीरंदाजी विश्व कप में दीपिका , अंकिता , बारी, अतनु व अभिषेक को प्रदर्शन हेतु दी बधाई

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पेरिस में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप में विलक्षण प्रदर्शन के लिए दीपिका कुमारी, अंकिता भाकत, कोमलिका बारी, अतनु दास और अभिषेक वर्मा को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, पिछले कुछ दिनों ने विश्व कप में हमारे तीरंदाजों का विलक्षण प्रदर्शन देखा है। दीपक, अंकिता भाकत, कोमलिका बारी, अतनु दास और अभिषेक को उनकी सफलता के लिए बधाई, जो इस क्षेत्र में आने वाली प्रतिभाओं को प्रेरित करेंगे।

बस को डीसीएम ने मारी टक्कर, पांच की मौत, दो घायल

फिरोजाबाद (आरएनएस)। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर थाना नगला खंगर क्षेत्र अन्तर्गत एक डबल डेकर बस में पीछे से डीसीएम ने टक्कर मार दी। हादसे में पांच लोगों की मौत हो गयी। जबकि दो लोग घायल हो गये। घायलों को सैफई उपचार के लिये भेजा गया है। एक डबल डेकर बस आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पर राजस्थान से लखनऊ जा रही थी। बस जैसे ही थाना नगला खंगर क्षेत्र अन्तर्गत पहुंची तभी बस के चालक राम सेवक को बस मे कुछ खराबी होने की आषंका हुई। जिस पर उसने बस को एक्सप्रेस वे पर रोक लिया और वह उसे ठीक करने लगा। बस की कुछ सवारियां उतर गयी थी। बताया जाता है कि तभी अचानक पीछे से तेज गति से आ रही एक डीसीएम ने बस में जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि बस चालक रामसेवक निवासी भरभंगा बिहार, डीसीएम चालक रेषम थापा निवासी नोएडा व परिचालक आनन्द निवासी गढवाल सहित दो अज्ञात लोगों की मौत हो गयी। जवकि दो लोग घायल हो गये। सूचना पर यूपीडा कर्मी व थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आनन फानन में घायलों को उपचार के लिये सैफई भिजवाने के साथ ही मृतकों के षवों को पोस्टमार्टम के लिये जिला अस्पताल भिजवाया। इस घटना पर प्रदेष के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गहरा दुख व्यक्त करते हुये अधिकारियों को घायलों का समुचित उपचार कराने के निर्देष दिये है।

एशिया के सबसे लंबे और दुनिया के पांचवां सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का हुआ उद्घाटन

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज इंदौर में एनएटीआरएएक्स- हाई स्पीड ट्रैक (एचएसटी)का उद्घाटन किया,जो एशिया का सबसे लंबा ट्रैक है। एनएटीआरएएक्स को1000 एकड़ भूमि के क्षेत्र में विकसित किया गया है। जहां पर 2 पहिया वाहनों से लेकर भारी ट्रैक्टर ट्रेलरों तक के सभी प्रमुख श्रेणी वाले वाहनों के हाई स्पीड परीक्षण हो सकेंगे। जो कि वाहनों के लिए सभी प्रकार के हाई स्पीड परीक्षण का एक प्रमुख केंद्र होगा। विश्व स्तरीय 11.3 किमी लंबे हाई स्पीड ट्रैक के ई-उद्घाटन पर बोलते हुए, जावड़ेकर ने कहा कि भारत का ऑटोमोबाइल और स्पेयर पार्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग केंद्र बनना तय है। मंत्री ने कहा, हम तेजी से आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं और इस दिशा में चौतरफा प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, उनका मंत्रालय प्रधानमंत्री के सपने को पूरा करने के लिए के लिए प्रतिबद्ध है जिसकेतहत भारत ऑटो मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा, ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग उद्योगों के विस्तार से नए रोजगार पैदा करने में भी सहयोग मिलेगा।

मंत्री ने कहा कि रेलवे, राजमार्ग और जलमार्ग क्षेत्र की कई परियोजनाएं वर्षों से लटकी हुई थीं जो आज मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति के कारण पूरी हो रही हैं।

इस अवसर पर भारी उद्योग एवंलोक उद्यम राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि सरकार मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमोबाइल उद्योग को बढ़ावा दे रही है क्योंकि इससे देश को बड़े पैमाने पर सशक्त बनाने में मदद मिलेगी।

एनएटीआरएएक्स केंद्र में कई परीक्षण क्षमताएं हैं जैसे अधिकतम गति को आंकना, एक्सीलरेशन,तय गति परईधन की खपत क्षमता, रियलरोड ड्राइविंग सिमुलेशन के माध्यम से उत्सर्जन परीक्षण, लेन बदलने के दौरान के दौरान वाहन की स्थिरता, उच्च गति की निरंतरता परखने की सुविधा है।इसके अलावा यह वाहनों के डायनेमिक्स काएक उत्कृष्टता केंद्र है।

एचएसटी का इस्तेमाल बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, ऑडी, फेरारी, लेम्बोर्गिनी, टेस्ला आदि जैसी हाई-एंड कारों की अधिकतम हाई स्पीड क्षमता को मापने के लिए किया जाता है। जिसे किसी अन्य भारतीय परीक्षण ट्रैक पर नहीं मापा जा सकता है। मध्य प्रदेश में स्थित होने के कारण, यह अधिकांश ओईएम के लिए सुलभ है। विदेशी ओईएम भी भारतीय परिस्थितियों के लिए प्रोटोटाइप कारों के विकास के लिए एनएटीआरएएक्स एचएसटी के इस्तेमाल पर विचार करेंगे। वर्तमान में, विदेशी ओईएम हाई स्पीड परीक्षण जरूरतों के लिए विदेश में उच्च गति वाले ट्रैक पर परीक्षण करते हैं।

यह सभी प्रकार के हाई स्पीड परीक्षणों के लिए एक प्रमुख स्थान है, जो दुनिया में सबसे बड़े ट्रैकों में से एक है। यह सभी तरह की श्रेणी वाले वाहनों की जरूरत को पूरा कर सकता है।दो पहिया वाहनों से लेकर सबसे भारी ट्रैक्टर ट्रेलरों तक के वाहनों का इस ट्रैक पर परीक्षण किया जा सकता है। ट्रैक के घुमावों पर वाहनोंकी स्टेयरिंग का नियंत्रण 375 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति पर भीकिया जा सकता है। इसके लिएट्रैक को कम अंडाकार बनाया गया है। जो इसे से वैश्विक स्तर पर सबसे सुरक्षित परीक्षण ट्रैक में से एक बनाता है।

संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से

» कोरोना की दूसरी लहर और महंगाई होगा विपक्ष का मुद्दा

नई दिल्ली (आरएनएस)। संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी (सीसीपीए) ने इस आशय की सिफारिश राष्ट्रपति को भेज दी है। सत्र में कुल 20 बैठकें होंगी। बीते कुछ सत्रों की तरह इस सत्र में भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। संभवतः संसद में प्रवेश करने वालों के लिए कोरोना का कम से कम एक डोज लेना अनिवार्य कर दिया जाएगा।

गौरतलब है कि कोरोना के कारण बीते दो सत्र को समय से पहले ही खत्म कर देना पड़ा था। इस बार ऐसी स्थिति नहीं आएगी। सत्र के दौरान 20 बैठकें आयोजित की जाएंगी। हालांकि संसद भवन में प्रवेश की सीमित संख्या पहले की तरह निश्चित की जाएगी।

दूसरी लहर के बाद पहला सत्र- अप्रैल और मई के मध्य आई कोरोना की दूसरी लहर के बाद संसद का यह पहला सत्र होगा। गौरतलब है कि दूसरी लहर के दौरान जानमाल की व्यापक क्षति हुई थी। इलाज और ऑक्सीजन के अभाव में कई लोगों की मौत हुई थी। ऐसे में विपक्ष की ओर से इस मुद्दे को व्यापक स्तर पर उठाए जाने की संभावना है। इसके अलावा विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था के सवाल पर सरकार को घेरेगा।

न्याय विभाग ने एनफोर्सिंग कॉन्ट्रेक्ट पोर्टल किया लॉन्च

नई दिल्ली (आरएनएस)। सचिव (न्याय) बरुन मित्रा ने दिल्ली स्थित न्याय विभाग में अन्य आला अधिकारियों की उपस्थिति में एक विशिष्ट एनफोर्सिंग कॉन्ट्रेक्ट्स पोर्टल का उद्घाटन किया। अनुबंध प्रवर्तन सम्बंधी इस पोर्टल का होमपेज नीचे दिया जा रहा है:-

विश्व बैंक समूह की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट दुनिया की 191 अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार को कानूनी तौर पर नियमित करने का मानदंड है। इसके तहत व्यापार सुगमता सूचकांक एक ऐसी रैंकिंग प्रणाली है, जिसके द्वारा किसी अर्थव्यवस्था के बारे में यह संकेत मिल जाता है कि व्यापार नियमन के 11 क्षेत्रों में वह अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में क्या हैसियत रखती है।अनुबंध प्रवर्तन संकेतक एक ऐसा अहम क्षेत्र है, जो मानक व्यापार विवादों के निपटारे में लगने वाले खर्च और समय के बारे में बताता है। इसके अलावा न्यायपालिका में उत्कृष्ट व्यवहारों के बारे में जानकारी देता है। मौजूदा समय में, सिर्फ दिल्ली और मुम्बई शहर को ही विश्व बैंक के व्यापार सुगमता सर्वेक्षण में शामिल किया गया है। कोलकाता और बेंगलूरू को भविष्य में डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में शामिल करने की संभावना है।

विधि और न्याय मंत्रालय का न्याय विभाग, नोडल विभाग होने के नाते भारत में व्यापार सुगमता के हवाले से अनुबंध प्रवर्तन को मजबूत बनाने के लिये विधायी और नीतिगत सुधारों की निगरानी करता है। इसका अर्थ यह है कि जिन पक्षों में किसी व्यापार का अनुबंध किया जाये, तो उसके सिलसिले में दोनों पक्ष अपना वायदा पूरा करें। इसमें उच्चतम न्यायालय और दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता और कर्नाटक के उच्च न्यायालयों की ई-समिति का सहयोग है। इन सबके साथ करीबी सहयोग की बदौलत न्याय विभाग विभिन्न सुधार उपायों का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है, ताकि कारगर, कुशल, पारदर्शी और मजबूत अनुबंध प्रवर्तन कानून बनाया जा सके।

31 जुलाई तक एक नेशन, एक राशन कार्ड योजना करें लागू : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रवासी मजदूरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश देते हुए कहा है कि सभी राज्य जुलाई 2021 तक एक नेशन एक राशन योजना लागू करें। इसके साथ ही केंद्र को राज्यों को अतिरिक्त अनाज आवंटित करने का निर्देश देते हुए कहा है कि राज्यों को प्रवासियों को सूखा राशन वितरण के लिए एक योजना लानी चाहिए। राज्यों को प्रवासी श्रमिकों के लिए महामारी के अंत तक सामुदायिक रसोई चलानी चाहिए। आदेश में यह भी कहा गया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों समेत सभी प्रवासी मजदूरों का पंजीकरण का काम 31 जुलाई 2021 तक पूरा करें।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना लॉकडाउन के कारण प्रवासी मजदूरों को हो रही समस्याओं पर स्वतः संज्ञान लेकर

सुनवाई शुरू की है। सुको ने 24 मई को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर की थी। कोर्ट ने कोविड-19 महामारी के दौरान देशभर में प्रवासी मजदूरों के पंजीकरण की धीमी प्रक्रिया पर नाराजगी जताई थी, साथ ही लेबर रजिस्ट्रेशन स्कीम के स्टेटस के बारे में केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। पिछले साल 2020 में कोरोना लॉकडाउन के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सभी प्रवासी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन करने का फैसला सुनाया था। प्रवासी श्रमिकों की दुर्दशा पर ध्यान देते हुए सुको ने कहा था कि उनके पंजीकरण की प्रक्रिया बेहद धीमी हो रही है और वह इस मामले पर केंद्र और राज्यों को निर्देश जारी करेगा।

हालांकि जस्टिस अशोक भूषण और एमआर शाह ने कहा था कि वह राहत पैकेज के तौर पर रुपये देने का आदेश नहीं देंगे क्योंकि ये एक नीतिगत निर्णय है। सुको ने कहा था कि केंद्र और राज्यों को प्रवासी कामगारों और असंगठित क्षेत्रों में काम करने वालों के पंजीकरण में तेजी लानी चाहिए। न सिर्फ प्रवासी मजदूर ही पंजीकरण के लिए सरकार से संपर्क करें, बल्कि सरकारों को भी उन्हें पंजीकृत कराने के लिए प्रवासियों से संपर्क करना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब प्रवासी मजदूरों का पंजीकरण हो जाए तो सरकारें उन प्रवासी कामगारों को लाभ दे सकती हैं, जिन्होंने महामारी के दौरान रोजगार खो दिया है। पीठ ने कहा था कि यह एक मुश्किल काम है, लेकिन इसे हासिल करना होगा। गौरतलब है कि पिछले साल जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को उन प्रवासी श्रमिकों की पूरी सूची तैयार करने का आदेश दिया था जो अपने राज्य में पहुंच गए हैं और लिस्ट में ये भी बताने को कहा था कि वह लॉकडाउन के दौरान क्या कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को लॉकडाउन के बाद इन प्रवासी कामगारों के रोजगार के लिए योजनाओं को निर्दिष्ट करने के लिए भी कहा था। इसके अलावा, केंद्र और राज्य सरकार को उन सभी कल्याणकारी योजनाओं का विवरण देने के लिए कहा गया, जिनका लाभ प्रवासी श्रमिक उठा सकते हैं।

अंबेडकर के समता मूलक समाज के मकसद को पूरा कर रही है भाजपा सरकार : कोविंद

लखनऊ (आरएनएस)। राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द ने कहा कि केन्द्र और उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) भगवान बुद्ध के वाक्य और भारत रत्न डा भीमराव अंबेडकर के उद्देश्य 'भवतु सब्ब मंगलम' को सही मायने में पूरा कर रही है।

लोकभवन में भारत रत्न डा. भीमराव अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र का वर्चुअल शिलान्यास किया। इस अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल,मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ,उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और डा दिनेश शर्मा मौजूद थे। श्री कोविंद ने कहा कि भगवान बुद्ध के वाक्य 'भवतु सब्ब मंगलम' का आत्मसात करना लोकतंत्र में हर सरकार का दायित्व है जिसका अर्थ है प्रजा की भलाई। भगवान बुद्ध के विचारों से प्रभावित डा अंबेडकर के समता मूलक समाज की परिकल्पना को भाजपा की सरकारें पूरा कर रही है। उन्होने कहा कि डा अंबेडकर ने 93 साल पहले आज ही के दिन समता मूलक समाज की परिकल्पना के साथ 'समता' नामक समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ किया। उनका संपूर्ण जीवन समता मूलक समाज की रचना में ही व्यस्त रहा। समाज मूलक समाज के मूल शिल्पी बाबा साहब ने संविधान में भी समता का जिक्र किया।

रेलवे 11,5000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 58 अति महत्वपूर्ण और 68 महत्वपूर्ण परियोजनाएं सौंपने के लिए तैयार

नई दिल्ली (आरएनएस)। भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मिशन मोड में भारतीय रेलवे अगले कुछ वर्षों में 11,5000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 58 अति महत्वपूर्ण और 68 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को सौंपने के लिए तैयार है। कोविड की चुनौतियों के बावजूद भारतीय रेलवे पटरियों की क्षमता बढ़ाने के लिए अत्यावश्यक परियोजनाओं को पूरा करने के लिए तेजी से काम कर रहा है।

पिछले एक वर्ष में 11,588 करोड़ रुपये की लागत वाली कुल 1,044 किलोमीटर लंबाई की 29 अति महत्वपूर्ण परियोजनाएं चालू हो गई हैं। भारतीय रेल ने 39,663 करोड़ रुपये

की लागत वाली कुल 3,750 किलोमीटर लंबाई की कुल 58 अति महत्वपूर्ण परियोजनाओं को चिन्हित किया है। इन 58 अति महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से 27 परियोजनाएं दिसंबर, 2021 तक पूरी हो जाएंगी जबकि शेष 02 परियोजनाएं मार्च 2022 तक सौंपी जाएंगी।

उल्लेखनीय है कि भारतीय रेल नेटवर्क का अधिकांश यातायात गोल्डन चतुर्भुज, उच्च घनत्व नेटवर्क मार्गों और अत्यधिक उपयोग किए गए भारतीय रेलवे नेटवर्क मार्गों पर चलता है। उच्च घनत्व और अत्यधिक उपयोग किए जाने वाले नेटवर्क मार्ग में भारतीय रेलनेटवर्क कीमार्ग लंबाई 51 प्रतिशत है लेकिन इसमें 96 प्रतिशत यातायात है।

यातायात घनत्व, ले जाई जाने वाली सामग्री के प्रकार, रणनीतिक दृष्टि से मार्ग के महत्व के आधार पर तेजी से प्रगति कर रही परियोजनाओं (व्यय पहले ही 60 प्रतिशत से अधिक) सहित तत्काल विस्तार के लिए आवश्यक परियोजनाओं को अति महत्वपूर्ण श्रेणी (58 परियोजनाएं) में रखा गया है। जो परियोजनाएं अगले चरण में पूरी होनी हैं उन्हें महत्वपूर्ण परियोजनाएं(68 परियोजनाएं) माना गया है। ये सभी सिविल परियोजनाएं (विद्युतीकरण तथा सिग्नलिंग कार्य से संबंधित) हैं।

केंद्रित रूप में वित्त पोषण तथा निरंतर निगरानी से इन परियोजनाओं को जल्द पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है ताकि निवेश का लाभ उठाया जा सके। पूरी होने पर यह परियोजनाएं मोबिलिटी, सुरक्षा में सुधार लाएंगी और इन संतृप्त तथा व्यस्त मार्गों पर सवारी और मालगाड़ी चलाने की अतिरिक्त क्षमता का निर्माण होगा। शीघ्र पूरी की जाने वाली चिन्हित परियोजनाओं के लिए बजट आवंटन को उच्च प्राथमिकता दी गई है।

अति महत्वपूर्ण परियोजनाएः- 39,663 करोड़ रुपए लागत की 3,750 किलोमीटर कुल लंबाई वाली 58 परियोजनाओं को अति महत्वपूर्ण चिन्हित किया गया है। यह अति महत्वपूर्ण परियोजनाएं मल्टी-ट्रैकिंग यानी दोहरीकरण/तीसरी लाइन/चौथी लाइन की व्यस्त मार्गों पर हैं। इन परियोजनाओं के पूरी होने पर रेलवे इन घने/ संतृप्त/व्यस्त मार्गों पर सुरक्षा के साथ तेज गति से अधिक यातायात संचालन में सक्षम होगा। अब तक 11,588 करोड़ रुपए लागत की 1,044 किलोमीटर कुल लंबाई की 29 परियोजनाएं चालू कर दी गई हैं। 27 परियोजनाएं दिसंबर, 2021 तक पूरी हो जाएंगी जबकि शेष 02 परियोजनाएं मार्च 2022 तक पूरी होंगी।

महत्वपूर्ण परियोजनाएं:- 75,736 करोड़ रुपये की लागत वाली 6,913 किलोमीटर कुल लंबाई की 68 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की पहचान की गई है और 1,408 करोड़ रुपये की लागत वाली 108 किलोमीटर लंबी 04 परियोजनाएं अब तक पूरी कर ली गई हैं और शेष परियोजनाओं को मार्च 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।